## प्रेस के लिए जानकारी नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 38/2021)

**तत्काल प्रकाशन के लिए**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "कम बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग की रूपरेखा" पर अनुशंसाएं जारी कीं ।

**नई दिल्ली 26 अगस्त 2021**- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "कम बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग की रूपरेखा" पर अनुशंसाएं जारी कीं ।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2020 के माध्यम से भादूविप्रा को भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत लाइसेंसिंग रूपरेखा पर अनुशंसाएं प्रदान करने का आग्रह किया ताकि वाणिज्यिक और नियंत्रित दोनों प्रयोगों के लिए कम बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी का प्रावधान किया जा सके।

3. कम बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित प्रस्तावित सेवाओं के संबंध में वर्तमान प्रावधान की बाधाओं पर विचार करते हुए दूरसंचार विभाग ने कहा है कि उचित लाइसेंसिंग रूपरेखा की आवश्यकता है और दूरसंचार विभाग की वर्तमान लाइसेंसिंग रूपरेखा के अंतर्गत सभी कारकों को समग्र रूप से विश्लेषित करने और सक्षम प्रावधानों की अनुशंसा करने, अथवा वाणिज्यिक और नियंत्रित दोनों प्रयोगों हेतु इस प्रकार की सेवाओं के लिए नई लाइसेंसिंग रूपरेखा का सुझाव दिए जाने, का आग्रह किया है।

4. कम बिट रेट की एप्लीकेशनों और आईओटी डिवाइसों को कम लागत, कम शक्ति और छोटे आकार के टर्मिनलों की आवश्यकता होती है जो न्यूनतम हानि के साथ सिगनलों को स्थानांतरित करने का कार्य प्रभावी रूप से कर सकें। आईओटी सेवाओं के लिए उपयुक्त, महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों वाले कम जनसंख्या वाले बहुत से क्षेत्रों में स्थलीय कवरेज या कनेक्टिविटी के अन्य रूपों की कमी हो सकती है । इसलिए सैटेलाइट सबसे अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में भी कवरेज प्रदान करके इस अंतराल को पूरा कर सकता है और भारत जोड़ो मिशन को पूरा करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

5. दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ के आधर पर "कम बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग की रूपरेखा" पर परामर्श पत्र 12 मार्च 2021 को जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं । इस परामर्श पत्र में सैटेलाइट आधारित कॉनेक्टिविटी, विभिन्न ओरबिट, कम बिट रेट की एप्लीकेशनों के लिए फ्रिक्वेंसी बैंड, सैटेलाइट क्षमताओं की उपलब्धता और लाइसेंसिंग रूपरेखा को सक्षम बनाने वाली आवश्यकताएं शामिल थीं ।

6. परामर्श पत्र पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 23 अप्रैल 2021 और 7 मई 2021 तक आमंत्रित की गई थीं । प्राधिकरण को विभिन्न हितधारकों से 29 टिप्पणियां और 4 प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुई। ये सभी टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 2 जून 2021 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का भी आयोजन किया गया था।

7. इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

क. आईओटी और कम बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के प्रावधानों के लिए उचित सेवा लाइसेंसधारी उनके अनुज्ञप्ति के क्षेत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के नेटवर्क मॉडल को कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है, जिसमें हाइब्रिड मॉडल, एग्रिगेटर मॉडल और डायरेक्ट-टू-सैटेलाइट मॉडल शामिल हैं।

ख. सभी प्रकार के सैटेलाइट जैसे जियो स्टेशनरी ओरबिट (जीएसओ) और नॉन-जीएसओ (एनजीएसओ) सैटेलाइट और किसी भी अनुमति प्राप्त सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी बैंड का प्रयोग सैटेलाइट आधारित कम बिट रेट की कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

ग. एकीकृत लाइसेंसिंग ढांचे के तहत प्रासंगिक मौजूदा प्राधिकारों को सैटेलाइट आधारित कम बिट रेट कॉनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए उचित प्रकार से संशोधित किया जा सकता है।

घ. एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत जीएमपीसीएस सेवा, वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा और एनएलडी सेवा और नियंत्रित वीसैट सीयूजी सेवा लाइसेंस को आईओटी डिवाइसों के लिए सैटेलाइट आधारित कम बिट रेट कनेक्टिविटी के प्रावधान को शामिल करने के लिए उचित प्रकार से संशोधित किया जा सकता है।

ड़. सेवा लाइसेंसधारी को सभी अनुमति प्राप्त सैटेलाइट बैंडों में विदेशी सैटेलाइटों से सैटेलाइट बैंडविड्थ को प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि सैटेलाइट आधारित सेवाओं को प्रदान किया जा सके। उन्हें अनुमोदित सूची में से विदेशी सैटेलाइट का चयन करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, जिसे सरकार द्वारा इसी उद्देश्य से प्रकाशित किया हो, और चुने गए विदेशी सैटेलाइट से प्रत्यक्ष रूप से सैटेलाइट क्षमता को लीज पर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और लीज पर ली गई क्षमताओं का प्रयोग करने से पहले उन्हें भारत में अर्थ स्टेशन को स्थापित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जो चुने हुए सैटेलाइट प्रणाली से संबंधित हो।

च. सरकार एक रूपरेखा को तैयार कर सकती है जिसमें कॉम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने का समय और भारत में घरेलू सैटेलाइट क्षमताओं की उपलब्धता शामिल है, ताकि सेवा लाइसेंसधारी अपनी क्षमता को प्राप्त करने की योजना बना सके और क्षमता खरीदारी को ईष्टतम बना सके।

छ. प्राधिकरण ने सेवाओं को सस्ता और किफायती बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाने की अनुशंसा की है जैसे 3-5 वर्ष की तुलना में एक लम्बे समय के लिए विदेशी क्षमताओं को किराए पर लेने की अनुमति देना, विदेशी सैटेलाइटों/सैटेलाइट प्रणालियों की अनुमोदित सूची में से विदेशी क्षमताओं को किराए पर लेते समय सरकार द्वारा लिए जाने वाले सुविधा

शुल्क को हटाना, चुने हुए विदेशी सैटेलाइटों से सीधे ही सैटेलाइट क्षमता को लीज पर लेना, बिचौलियों की भूमिका को कम करना और वर्तमान एनओसीसी शुल्कों को खत्म करना।

ज. व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) में सुधार करने के लिए यह भी अनुशंसा की जाती है कि दूरसंचार विभाग को विभिन्न अनुमोदनों/अनुमतियों/आबंटन आदि के अनुदान में शामिल सभी एजेंसियों, जैसे डीओएस, डीओटी, डबल्युपीसी और एनओसीसी, आदि के लिए 'एकल खिड़की ऑनलाइन कॉमन पोर्टल' का निर्माण करना चाहिए, जहां सेवा लाइसेंसधारी अपना निवेदन कर सकें और एजेंसियां एक पारदर्शी और समय सीमा के अंदर ऑनलाइन अनुक्रिया कर सकें। सभी दिशानिर्देशों, आवेदन प्रपत्रों, शुल्क विवरण, प्रक्रियाओं, समय सीमाओं और आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर पारदर्शी रूप से उपलब्ध किया जाना चाहिए।

8. "कम बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग की रूपरेखा" पर अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर भी उपलब्ध कराया गया है।

9. स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, यदि कोई है, श्री एस.टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से advmn@trai.gov.in या टेलीफ़ोन नंबर +91-11-23210481 सम्पर्क किया जा सकता है

**(वी. रघुनंदन)**
**सचिव, भादूविप्रा**